

जल समाचार

पवन कुमार

गर्मियों में भी गंगा-यमुना में रहे भरपूर पानी

गर्मियों के मौसम में भी अब मैदानी इलाकों में जाकर गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर कम नहीं होगा। नदियों में पानी का एक समान स्तर बनाए रखने की कवायद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। मंत्रालय इस सिद्धांत पर अमल करना चाहता है कि इन दोनों नदियों पर सिंचाई और जल विद्युत की जो भी परियोजनाएं बनी हैं, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा नहीं किया जाए। ऑफ सीजन (गर्मियों में) में समय पर पानी की एक निश्चित मात्रा नदी में छोड़ी जाए। इसको लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि गंगा का ई फ्लो (पर्यावरणीय बहाव) बरकरार रखा जाए। ई फ्लो प्रभावित होने से नदी में वास करने वाले जलीय जंतुओं का संसार प्रभावित हो रहा है। नदी में पानी की मात्रा कम होने से जलीय जंतुओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसमें पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित कई मुद्दे भी शामिल हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह ने पिछले दिनों संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने निर्देश दिया कि गंगा और यमुना नदी पर जो भी सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, उससे ऑफ सीजन में 15 से 20 फीसदी पानी छोड़ा जाए। इसको लेकर उन्होंने राज्य सरकारों से सुझाव मांगा है ताकि इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके।



बाढ़-सूखे की तबाही रोकेगा एनआईएच

देश में हर साल बाढ़ और सूखे से होने वाली तबाही रोकने में अब रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) के वैज्ञानिक मदद करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया है। आठ साल की अवधि वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 3640 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका आधा खर्च विश्व बैंक वहन करेगा।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग डॉ. अनिल कुमार लोहनी ने परियोजना के बाबत बताया कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का जो मसौदा तैयार किया है उसके तहत संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। कार्यक्रम के तहत बाढ़ प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों और अफसरों को यह जानकारी दी जाएगी कि नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही को कैसे कम किया जाए और नदियों के पानी को कैसे नियंत्रित किया जाए। इस दौरान रीवर बेसिन मैनेजमेंट के साथ ही भूमिगत जल के प्रबंधन से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारियां मुहैया करायी जाएंगी। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डॉ. लोहनी के मुताबिक इस परियोजना में विश्व बैंक 1820 करोड़ की वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है जबकि इतना ही बजट केंद्र सरकार देगी। जहां तक राज्यों का सवाल है तो राज्यों को एक भी रूपया नहीं खर्च करना है। केंद्र सरकार राज्यों को पूरी वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।

बढ़ते तापमान से बढ़ा बाढ़ का खतरा

एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण इन देशों में तापमान बढ़ने के साथ बाढ़ का खतरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है।

आयरलैंड, नीदरलैंड की तकनीक होगी इस्तेमाल

ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डॉ. लोहनी के मुताबिक फ्लड मैनेजमेंट के क्षेत्र में आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों ने अच्छा काम किया है इन देशों में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को देश में भी इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अलावा देश के अन्य वैज्ञानिक तकनीकी दक्षता हासिल कर सकें इसके लिए यूनेस्को, आइएचई में भी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

नाकामी पर सीएजी ने जतायी थी नाराजगी

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सालाना रिपोर्ट में देश में बढहाल फ्लड मैनेजमेंट पर गहरी नाराजगी जता चुके हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात जैसे राज्य देश की जीडीपी में 27 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन बेहद खराब फ्लड मैनेजमेंट और बजट का सही इस्तेमाल नहीं करने से इन राज्यों के करोड़ों लोगों को बाढ़ से होने वाली तबाही का सामना करना पड़ता है। सीएजी रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन को लेकर तमाम राज्यों में संचालित प्रोजेक्ट के बंद होने पर भी गहरी नाराजगी जता चुका है।

कई राज्य कर रहे फ्लड बिल का विरोध

बाढ़ से होने वाली तबाही से लोगों को बचाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने 1975 में मॉडल फ्लड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन चार दशक बीतने के बावजूद इस बिल को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। इस बिल के लागू होने के बाद अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में बस्तियों को जबरन हटाने का अधिकार होगा और इन बस्तियों के लोग दोबारा वहां नहीं बस सकेंगे। कई राज्य इस तर्क के साथ इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों को विस्थापित करने के बाद बसाया कहा जाएगा।

एनआईएच कर्मचारियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं और शौचालय आदि की सफाई की। संस्थान की ओर से इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान पर एक कला प्रतियोगिता भी कराई गई।

इस मौके पर डॉ. एल एन ठकुराल ने कहा कि जहां पर स्वच्छता होती है वहां पर स्वयं ही खुशहाली आ जाती है। इस मौके पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. एआर सैथिल कुमार, एस के वर्मा, डॉ. पी के सिंह, वी के शर्मा, एम के शर्मा, एस के सत्यार्थी, दौलत राम, अलका, सीमा आदि मौजूद रहे। उधर, द ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल की ओर से भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत चुडियाला स्टेशन पर सफाई की गई। बच्चों ने झाड़ू लेकर स्टेशन को साफ किया। साथ ही आसपास के गांव में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर विद्यालय की संचालिका डॉ. शालिनी पंत, प्रदीप चौधरी, प्रधानाचार्य एस के दहिया सहित अन्य मौजूद रहे।



शिलांग में बैंक फिल्ट्रेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की ने लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग शिलांग, मेघालय में 18 से 22 सितंबर, 2017 के दौरान निरंतर पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बैंक फिल्ट्रेशन पर 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, मेघालय, उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय, ड्रेस्टेन, जर्मनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उत्तराखंड जल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था।

यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया और परियोजना नीरविन्दू (NIRWINDU) के वैज्ञानिक सहयोग जर्मन शैक्षणिक एक्सचेंज सेवा द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड में शिक्षा और अनुसंधान के जर्मन संघीय मंत्रालय (बीबीएमएफ) और सतत पेयजल आपूर्ति द्वारा वित्त पोषित, (डीएएडी) था।

रिवर बैंक निर्यंदन (आरबीएफ) या बैंक निर्यंदन (Bank Filtration-बीएफ), एक प्राकृतिक पूर्व उपचार तकनीक के रूप में, नदी और अन्य सतह जल निकायों के लिए एक एकीकृत शब्द का उपयोग यूरोप में कई दशकों तक किया जाता है ताकि सतह पर स्थित समुदायों को पेयजल प्रदान किया जा सके। जल निकायों, आमतौर पर नदियों के पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसके आगे के विकास के लिए कई नगरों और शहरों में वर्तमान में पेयजल का उपयोग करते हुए पीने के पानी की उपलब्धता के लिए उनके सार्वजनिक जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में सिस्टम के वैज्ञानिक और तकनीकी हिस्से को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में निगरानी रखने पर यह देखा गया कि जब सतह या भूजल स्रोतों से सीधा पानी के साथ तुलना की जाती है तो कुछ साइटों से पानी में काफी उच्च गुणवत्ता दिखाता है। कई रिपोरियन भारतीय शहरों/कस्बों में हाइड्रोजिओलॉजिकल परिस्थितियों ने संकेत दिया था कि ये शहर/कस्बे बीएफ प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त होंगे। हालांकि बीएफ प्रणालियों को पूरे राष्ट्र में पानी की आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार के लिए एक महान क्षमता के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसी प्रणालियों की स्थिरता के बारे में एवं कई व्यावहारिक मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत के कई संभावित क्षेत्रों में अपनी गुंजाइश और स्केलिंग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सतत पेयजल आपूर्ति के लिए रिवर बैंक फिल्ट्रेशन (आरबीएफ)

करने पर देशव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम नामक एक परियोजना को डॉ. एन. सी. घोष वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रभागाध्यक्ष भूजल जलविज्ञान के नेतृत्व में मंजूरी दी है। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना के चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरा है। रुड़की और गोवा में अन्य 2 कार्यक्रम पहले से ही आयोजित किए जा चुके हैं।

पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे

- बीएफ, इसकी भौतिक प्रक्रियाओं, और इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के साथ प्रतिभागियों को परिचय कराना।
- बीएफ सिस्टम के नियोजन, डिजाइन, निर्माण और संचालन पर ज्ञान
- बैंक फिल्ट्रेशन योजना के जोखिम और बाद के उपचार के आंकलन और आइसोटोप के अनुप्रयोगों के तरीकों को हाईलाइट करना।
- बैंक योजना-पूफिंग, संरक्षण और व्यापक जल गुणवत्ता मूल्यांकन।
- यूरोप में बीएफ योजना के साथ अनुभव और भारत में बीएफ पर मौजूद केस स्टडी।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान सचिव, श्री डी.पी. वाहलॉंग द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और मणिपुर के 22 प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम में प्रतिभाग किया।

कोर्स में विशेष रूप से एनआईएच, आईआईटी रुड़की, यूजेएस और यूकोस्ट जर्मनी और भारत के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन किया। इसके अलावा एक दिवसीय तकनीकी क्षेत्र यात्रा का आयोजन डब्ल्यूटीपी, माफ्लैंग और चेरापूंजी में किया गया था।

महानिदेशक, UCOST डॉ. राजेन्द्र डोभाल ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये।



भारत जल सप्ताह 2017 का आयोजन

भारत जल सप्ताह-2017 का शुभारंभ 10 अक्टूबर 2017 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया इस जल सप्ताह का मुख्य थीम “समावेशी विकास के लिए जल एवं ऊर्जा” था। इस पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत सहित 13 अन्य देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग व शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत 27 परियोजनाएं इस साल तक पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए अगले साल तक 285 नई सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि बूंद-बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई और पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में होगी क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में पानी की बचत होगी और इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण में निहित लागत भी घट जाएगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जल, बिजली, परिवहन और संचार विकास के चार सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के हालिया उद्घाटन का उल्लेख किया जो 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को पानी मुहैया कराएगी और 8 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा सुलभ कराने में मदद करेगी।



श्री गडकरी ने कहा कि बाढ़ और सूखे से लोगों को बचाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 30 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है जिनमें से तीन परियोजनाओं यथा केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा-पिंजल परियोजनाओं



पर काम तीन माह के भीतर शुरू हो जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ा कोष बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। श्री गडकरी ने कहा कि शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि उन्होंने एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों में पुनरावर्तित (रिसाइकिल्ड) पानी का उपयोग करने की संभावना तलाशने के लिए विद्युत मंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने नदी के 70 फीसदी पानी का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जो समुद्र में चला जाता है। पंचेश्वर परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय में सचिव जल्द ही लॉन्च मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल का दौरा करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि परियोजना पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। श्री गडकरी ने यह भी उम्मीद व्यक्त की कि भारत जल सप्ताह के दौरान होने वाले विचार विमर्श और चर्चाओं से कुछ अच्छे सुझाव सामने आएंगे।

केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक देश के हर घर में सुरक्षित पेयजल और प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। उन्होंने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। हमने भूजल का दुरुपयोग किया है एवं इसे बर्बाद किया है। हमें पानी, नदियों एवं भूजल का सम्मान करना होगा और देश में बहने वाली नदियों को अवरिल एवं निर्मल बनाना होगा।

भारत जल सप्ताह-2017 के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जल और ऊर्जा दो महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनका समुचित संरक्षण और इष्टतम उपयोग राष्ट्र के समेकित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के 112 जिलों में 20 प्रतिशत से भी कम सिंचाई कवरेज है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी की कमी और बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए समयबद्ध उपायों की जरूरत है। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने भूजल के टिकाऊ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना का प्रस्ताव किया है जो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 6,000 करोड़ रुपये की योजना है।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2017 में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि पानी और ऊर्जा के बुनियादी मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित सत्र नीति निर्माताओं और राष्ट्र के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होंगे। भारत जल सप्ताह-2017 में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. शरद कुमार जैन सहित डॉ. एन.सी. घोष, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. सी.के. जैन, डॉ. जयवीर त्यागी, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. वी.सी. गोयल, डॉ. सी.पी. कुमार, डॉ. संजय कुमार जैन, डॉ. एम.के. गोयल, डॉ. सुहास खोब्रागडे, डॉ. अनुपमा शर्मा, डॉ. संजय कुमार, डॉ. सुरजीत सिंह, डॉ. एम.के. शर्मा, डॉ. वी. चक्रवर्ती, डॉ. वाई.आर.एस. राव, डॉ. वी. वैकटेश डॉ. तेजराम नायक ने भी प्रतिभाग किया।

संपर्क करें:

पवन कुमार, सह-संपादक जल चेतना
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की-247667, हरिद्वार, उत्तराखंड
मो.नं. 9359729313, 01332-249267
ईमेल: pksharma019@gmail.com